गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 226
दि. 17.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई से दिल्ली कोर्ट का इनकार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है, ऐसे में इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जबकि ईडी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई तभी संभव है, जब कोई अनुसूचित अपराध दर्ज एफआईआर के जरिए सामने आया हो। अदालत ने माना कि नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से शुरू हुआ था और इसे सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस से जुड़े अन्य नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। इस

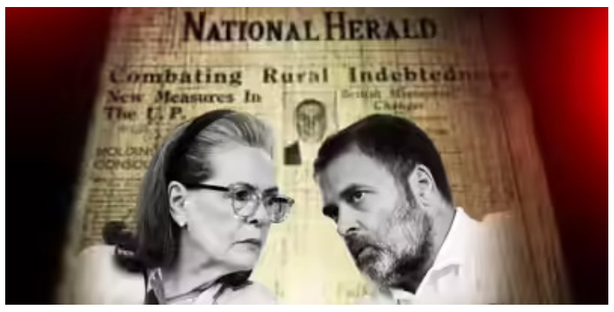

केस में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और इसके प्रमोटर सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप यह है कि घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार के जरिए एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रची गई।

इसी मामले में अदालत ने एक और अहम आदेश देते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एफआईआर की कॉपी देने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश को भी रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस की दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को केवल एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन वे एफआईआर की कॉपी पाने के हकदार नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि कानून के तहत इस स्तर पर एफआईआर की प्रति देना जरूरी नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत के आधार पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज, इसके प्रमोटर सुनील भंडारी, एजेएल और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये सभी नाम ईडी की ओर से अप्रैल में दाखिल की गई चार्जशीट में भी शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के जरिए अपने कब्जे में लिया। आरोपों के मुताबिक, इसके लिए यंग इंडियन लिमिटेड नाम की संस्था बनाई गई, जिसमें गांधी परिवार की बहुलांश हिस्सेदारी है। इसी संस्था के जरिए एजेएल का कथित रूप से अवैध अधिग्रहण किया गया। स्वामी का दावा था कि यह पूरा मामला दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने से जुड़ा है और 2,000 करोड़ की कंपनी को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल किया गया। अदालत के ताजा फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे 'सत्य की जीत' बताया है। पार्टी ने कहा कि इस निर्णय से मोदी सरकार की दुर्भावनापूर्ण राजनीति और कथित गैरकानूनी कार्रवाइयों का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला बनता है, न ही अपराध से अर्जित धन का कोई सबूत मौजूद है और न ही किसी संदिग्ध लेन-देन का प्रमाण मिला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक दबाव और बदनाम करने के उद्देश्य से खड़ा किया गया था। वहीं, ईडी ने साफ किया है कि वह इस मामले को यहीं खत्म नहीं मानेगी। एजेंसी का कहना है कि कोर्ट का फैसला तकनीकी आधार पर आया है और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नई एफआईआर दर्ज कर ली है और जैसे ही कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, ईडी दोबारा चार्जशीट दाखिल करेगी। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच जारी रहेगी और वह अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। इस फैसले के बाद नेशनल हेराल्ड मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में आ गया है। जहां कांग्रेस इसे अपनी नैतिक और कानूनी जीत बता रही है, वहीं जांच एजेंसियां इसे केवल एक अस्थायी राहत मानते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी हैं। आने वाले समय में इस मामले पर अदालतों में एक बार फिर लंबी कानूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चव्हाण का तीखा बयान पहले ही दिन हार का दावा, सियासी घमासान तेज

(जीएनएस)। पुणे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारतीय वायुसेना को हार का सामना करना पड़ा था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और भारतीय सेना की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है।

पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि 7 मई को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारत की स्थिति मजबूत नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस दिन भारतीय वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर रही और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। चव्हाण के मुताबिक, यदि ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा जैसे एयरबेस से कोई विमान उड़ता, तो पाकिस्तान द्वारा उसे मार गिराए जाने की संभावना काफी अधिक थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय विमानों को मार गिराया

गया और इस वजह से एयरफोर्स को पूरी तरह से जमीन पर रखने का फैसला किया गया।

चव्हाण ने अपने बयान में कहा कि लोग चाहे इसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को झटका लगा था। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो कुछ भी हुआ, वह हवाई और मिसाइल युद्ध तक सीमित रहा। जमीनी स्तर पर सेना की कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब आधुनिक युद्ध अब तकनीक, मिसाइल और एयर पावर पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में भी इतनी बड़ी थल सेना की आवश्यकता रहेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की एक किलोमीटर तक की भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। उनके मुताबिक, दो या तीन दिनों तक जो घटनाक्रम चला, वह पूरी तरह से हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित था। इस आधार पर उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या देश को 12 लाख सैनिकों की विशाल सेना बनाए रखने की जरूरत है, या फिर भविष्य में सैन्य ढांचे को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता होगी। पृथ्वीराज चव्हाण ने इसी क्रम में देश की परमाणु नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुए पोखरण परमाणु परीक्षण को ऐतिहासिक भूल करार दिया। चव्हाण ने कहा कि उस समय यह केवल अटकलें थीं कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण कर दिए और दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गए। उनके अनुसार, इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और सुरक्षा चुनौतियां और जटिल हो गईं।

चव्हाण के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। पुणे बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बयान का वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है और वे पाकिस्तान के सैन्य दावों पर ज्यादा यकीन करते हैं। पार्टी ने कहा कि भारतीय सेना पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हुए नुकसान की जानकारी सार्वजनिक कर चुकी है, इसके बावजूद इस तरह के बयान देश के मनोबल को कमजोर करने वाले हैं।

बीजेपी नेताओं ने इसे सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाला बयान बताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदार पदों पर रह चुके नेताओं को बेहद सतर्क भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

मुंबई को एम्स की दरकार, लोकसभा में गूंजा महानगर के लिए विश्वस्तरीय स्वास्थ्य संस्थान का मुद्दा

(जीएनएस)। मुंबई/नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को लेकर लोकसभा में जोरदार आवाज उठी है। मंगलवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद रविंद्र वायकर ने सदन में वित्त वर्ष 2025-26 की पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की तेजी से बढ़ती आबादी और गंभीर बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां एक नए एम्स की स्थापना समय की मांग बन चुकी है। उन्होंने इसे केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक राष्ट्रीय महत्व का चिकित्सा संस्थान बताया।

सांसद रविंद्र वायकर ने अपने संबोधन में विशेष रूप से कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एम्स को ऑन्कोलॉजी और कैंसर रिसर्च के लिए एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ देश के सबसे प्रतिष्ठित कैंसर संस्थानों में से एक टाटा मेमोरियल अस्पताल पर मरीजों का बोझ कम

होगा, बल्कि लाखों ऐसे मरीजों को भी राहत मिलेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। वायकर ने कहा कि अगर मुंबई में एम्स की स्थापना होती है तो मध्यम और गरीब वर्ग के मरीजों को भी मुफ्त और विश्वस्तरीय इलाज मिल सकेगा। उन्होंने मुंबई को देश की 'मेडिकल राजधानी' बताते हुए कहा कि यहां देश के कोने-कोने से मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन मौजूदा ढांचा बढ़ते दबाव को संभालने में असमर्थ होता जा रहा है। टाटा मेमोरियल अस्पताल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि परेल स्थित इस अस्पताल के बाहर हर दिन मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ देखी जा सकती है। कई बार सड़कें तक भर जाती हैं और दूर-दराज से आए कैंसर रोगियों को ठहरने और इलाज के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति साफ संकेत देती है कि मुंबई जैसे महानगर में केवल एक बड़े कैंसर संस्थान के भरोसे काम नहीं चल सकता।

रविंद्र वायकर ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की है और 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं का उद्देश्य भी यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक बेहतर इलाज पहुंचे। ऐसे में मुंबई में एम्स की स्थापना इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने का बड़ा कदम साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि एम्स जैसे संस्थान न केवल इलाज करते हैं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, शोध और नई तकनीकों के विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसका सीधा लाभ पूरे देश को मिलता है।

अपने भाषण में सांसद ने यह भी कहा कि नया एम्स बनने से मुंबई के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती मिलेगी। इससे एक तरफ टाटा मेमोरियल अस्पताल पर निर्भरता कम होगी, तो दूसरी ओर शहर में स्वास्थ्य सेवाओं का संतुलन बेहतर होगा। उन्होंने तर्क दिया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की आबादी कई राज्यों से भी अधिक है, ऐसे में यहां एम्स जैसे संस्थान का होना पूरी तरह जायज और जरूरी है।

वायकर ने अंत में केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस मांग पर गंभीरता से विचार करे और मुंबई के लिए एक समर्पित एम्स की घोषणा करे। उनका कहना था कि यह सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगा। लोकसभा में उठी इस मांग के बाद अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के रुख पर टिकी हैं कि वह देश की इस सबसे बड़ी महानगर की स्वास्थ्य जरूरतों को लेकर क्या फैसला करती है।

नगर निकाय चुनावों की आहट के साथ महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज

(जीएनएस)। कोल्हापुर। राज्य की मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के कामकाज से असंतोष को आधार बनाते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी ने आगामी नगर निकाय चुनावों में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया है। पार्टी पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर और इचलकरंजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार उतारेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में बुधवार को कोल्हापुर में नगर निगम चुनाव का औपचारिक बिगुल फूंका जाएगा। यह जानकारी कोल्हापुर मेट्रोपॉलिटन सिटी अध्यक्ष अरुण सोनवणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जनता पारंपरिक पार्टियों से निराश है और ऐसे में वंचित बहुजन अघाड़ी एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के रूप में सामने आ रही है। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वंचित बहुजन अघाड़ी को बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के साथ किसी संभावित गठबंधन में जगह मिलेगी या वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। नागपुर। राज्य में नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नागपुर नगर निगम के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बीजेपी नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का अंतिम चयन पार्टी संगठन की राय, जमीनी सर्वे रिपोर्ट और महायुति की नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व का फोकस ऐसे उम्मीदवारों पर है, जो संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ चुनाव में जीत सुनिश्चित कर सकें। चुनावी घोषणा के साथ ही नागपुर में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और दावेदारों की सक्रियता भी साफ नजर आने लगी है।

मुर्तिजापुर। नगर परिषद चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मुर्तिजापुर के चार पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अकोला जिले के मुर्तिजापुर नगर परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इन पदाधिकारियों को छह साल के लिए निष्कासित किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष शिवरकर ने बताया कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। निष्कासित किए गए नेताओं में मंडल कार्यकारी उपाध्यक्ष कमलाकर गावंडे, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमोल पिंपले, बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्रीकांत रामेकर और नमामि गंगे अभियान प्रमुख नितिन भटकर शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई संगठन में अनुशासन बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।

नगर निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच इन घटनाक्रमों से साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में मुकाबला और तेज होने वाला है, जहां एक ओर नई और क्षेत्रीय ताकतें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी ओर बड़ी पार्टियां संगठनात्मक मजबूती और अनुशासन के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी हैं।

मनरेगा के नाम बदलने पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम, लोकसभा में 'VB-जी राम जी' बिल पेश होते ही हंगामा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-जी राम जी बिल, 2025' पेश किए जाने के साथ ही संसद में तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई। जैसे ही यह विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने की साजिश करार दिया। सदन में नारेबाजी और हंगामे के बीच कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर मनमानी और बिना व्यापक चर्चा के ऐतिहासिक कानून में बदलाव करने का आरोप लगाया।कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को हर योजना का नाम बदलने की सनक क्यों सवार है, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा, बिना सलाह और बिना स्थायी समिति को भेजे इस तरह का विधेयक लाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने भावुक लहजे में कहा कि महात्मा गांधी किसी एक परिवार के नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं और उनके नाम से जुड़ी योजना को हटाने या बदलने का फैसला देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने सरकार से इस विधेयक को वापस लेने और नए सिरे से व्यापक विचार-विमर्श के बाद बिल लाने की मांग की। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कोई भी कानून किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक या पूर्वाग्रह के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस बिल को कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाए, ताकि इसके सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार हो सके। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों का कानूनी अधिकार है, जिसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी VB-जी राम जी बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम किसी भी तरह से हटाना या बदलना गलत है। थरूर ने सदन में कहा कि गांधीजी का नाम किसी राजनीतिक विजन से नहीं, बल्कि सामाजिक विकास, नैतिकता और मानवीय मूल्यों से जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि राम का नाम लेकर किसी ऐसे कदम को सही ठहराने की कोशिश न की जाए, जिससे गांधीजी के नाम और उनके विचारों को हाशिए पर डालने का आभास हो। सरकार की ओर से पेश किए गए बिल में कहा गया है कि यदि VB-जी राम जी कानून पास होता है, तो यह मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की जगह लेगा। नए विधेयक का उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास के लिए एक नया ढांचा तैयार करना बताया गया है। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि ग्रामीण रोजगार के तहत मिलने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी, जिसे सरकार ग्रामीणों के लिए एक अतिरिक्त लाभ के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि नाम बदलने के पीछे असली मंशा मनरेगा की मूल भावना और उसके कानूनी स्वरूप को कमजोर करना है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार धीरे-धीरे मनरेगा जैसे जनहितकारी कानून को समाप्त करना चाहती है और उसकी जगह एक ऐसी योजना लाना चाहती है, जिसमें गरीबों का अधिकार सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। संसद के बाहर भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह बुधवार, 17 दिसंबर को देशभर में VB-जी राम जी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि हर जिले के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं।

संपादकीय

सिडनी में खूनी खेल

सिडनी में यहूदियों को निशाना बनाये जाने की घटना ने पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों को हरा कर दिया। पहलगाम में भी आतंकियों ने लोगों को चुन-चुनकर मारा था। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय की सभा पर हुआ हमला हमें इस क्रूरता की याद दिलाता है कि आतंकवादी आम जीवन के केंद्र में, प्रार्थना स्थलों और सुकून देने वाले स्थलों को ही अपना निशाना बनाते हैं। यह हिंसा उस हनुक्का उत्सव के दौरान की गई, जो अंधकार के साम्राज्य को प्रकाश से पराजित करने का संकल्प दर्शाता है। इस मायने में यह हमला क्रूरता की हद दर्शाता है। दरअसल, आस्ट्रेलिया लंबे समय से इस विश्वास के चलते शांति का अहसास करता रहा है कि तमाम वैश्विक संघर्षों से बनायी गई उसकी दूरी, उसे सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इस घटना के बाद उसका भ्रम टूटा है। अब जाकर उसे यह अहसास हुआ है कि आतंकवादी अपने घातक मसूंबों को अंजाम देने के लिये हमारे ऐसे ही विश्वासों को तोड़कर हमले करते हैं। बॉन्डी के हमले ने न केवल आस्ट्रेलिया के भ्रम को तोड़ा है बल्कि उसे अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव को बाध्य किया है। जैसा कि अपरिहार्य है, आस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने हमले को एक वैश्विक आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया है। खासकर हिंसा के तौर-तरीके और वैचारिक मकसद को ध्यान में रखते हुए। यह वर्गीकरण इस बात को भी स्वीकार करता है कि हमला नफरत से प्रेरित हिंसा के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा था,जो दुनिया के तमाम देशों में देखा जा रहा है। इस आतंकी घटना के बाद यहूदी समुदाय में दुख के साथ-साथ आक्रोश भी उमड़ रहा है। खासकर इस बात को लेकर कि यहूदी समुदाय द्वारा लंबे समय से दी जा रही चेतावनी के बावजूद आस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी रवैये को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस प्रवृत्ति पर पहले से ही सतर्क निगरानी रखी गई होती तो शायद बॉन्डी के हमले को टाला जा सकता।

निस्संदेह, आस्ट्रेलिया में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। हालांकि, यहां हुए अधिकांश विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन चरमपंथी विचारधारा का पोषण करने वाले मुट्ठीभर लोग भी घातक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। यह हमला ऐसे मंसूबों की रोकथाम की सीमाओं को भी उजागर करता है। निस्संदेह, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से आंतकी नेटवर्क की निगरानी समय रहते की जा सकती है। वे सही वक्त पर ही न केवल आने वाले खतरों का आकलन कर सकती हैं बल्कि साजिशों को नाकाम भी कर सकती हैं। लेकिन एक विसंगति यह भी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अकेले हमले करने वालों को रोकना कुछ कठिन जरूर होता है। जैसे कि इस मामले में देखने में आया है। फिर भी, इस भयावह घटना के बीच एक साहस देखने को भी मिला। एक बहादुर राहगीर ने एक हमलावर को निहत्था करने के लिये अपनी जान भी जोखिम में डाली। हालांकि, वह इस प्रयास में घायल हुआ, लेकिन वह कई लोगों की जान बचाने में कामयाब हुआ। पूरी दुनिया में उसके साहस के लिये प्रशंसा हो रही है। संकट की घड़ी में ऐसा साहस आतंकवादियों की कायरता पर करारा प्रहार होता है और इससे आतंकवादियों के मंसूबे धरे रह जाते हैं। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि घोर अंधकार के क्षणों में भी मानवता का अंत नहीं होता। निश्चित रूप से इस घटना के बाद आस्ट्रेलिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके यहां रह रहे संवेदनशील समुदायों के लिये मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही समय रहते समाज में घृणा को बढ़ाने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे वक्त में जब हमास व इस्राइल के संघर्ष के बाद पूरी दुनिया में यहूदी विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर साझा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विश्व समुदाय को किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ होने वाली आतंकी घटनाओं का मुकाबला मिलकर करने की जरूरत है। अन्यथा कट्टरपंथी तत्वों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। इसके अलावा आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद, समर्थन व अन्य सहयोग देने वाले देशों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है।

नितिन नवीन की ताजपोशी के मायने

> हाल के दिनों में बीजेपी में पिछड़ा नेतृत्व पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया। इससे बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक दबे स्वर से नाराजगी भी जाहिर करता रहा है। विराट उभार से पहले बीजेपी को बाभन-बनिया की पार्टी भी कहा जाता था। इसमें कायस्थ और किंचित क्षत्रिय वर्ग भी जुड़ा हुआ था।

नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी का जब इतिहास लिखा जाएगा, तब उसकी तमाम खूबियों और खामियों के साथ एक तथ्य को शिद्दत से याद किया जाएगा। वह है पार्टी का हर बार चौंकाने वाला फैसला लेना। राजनीति के लिहाज से 45 साल की उम्र युवा मानी जाती है। राजनीति में युवाओं को शीर्ष पर बैठाने की परंपरा कम ही रही है। लेकिन बीजेपी ने 45 साल के नितिन नवीन को अपना बॉस घोषित कर दिया है। नितिन को फिलहाल पार्टी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी के आखिर तक उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाएगा। नितिन की ताजपोशी पर चर्चा से पहले बीजेपी से ही जुड़े अतीत के एक किस्से को याद कर लिया जाना चाहिए। मई 1996 में तेरह दिनी वाजपेयी सरकार के विश्वासमत पर चर्चा के दौरान सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व से पूछा था, कहां है आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। हमारी ओर देखिए, वेंकैया हैं, अनंत हैं, प्रमोद हैं। अटल-आडवाणी और जोशी के दौर की बीजेपी में बिना शक ये तीनों ही नाम शीर्ष नेतृत्व में शामिल थे। पार्टी की दूसरी पांत के नेताओं में सुषमा के बताए तीन नामों के साथ ही उनका भी नाम भी शामिल था। बाद के दिनों में अरूण जेटली को भी इसी पंक्ति में शामिल कर लिया गया था। ऐसे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या नितिन नवीन का नाम दूसरी पंक्ति के नेताओं में शुमार होता है। निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। भले ही वे पांच बार के विधायक हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम इतना चर्चित नहीं रहा है। बीजेपी के मुख्य संगठन में छत्तीसगढ़ के प्रभार की जिम्मेदारी छोड़ दें तो इसके पहले कोई बड़ी भूमिका भी नहीं सौंपी गई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बिहार इकाई के वे अध्यक्ष और इसी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री जरूर रहे हैं। युवा मोर्चा संभालना और मुख्यधारा के संगठन को संभालना अलग -अलग है। ऐसे में नवीन के सामने बड़े और दिग्गज नेताओं से भरी बीजेपी को संभालना बड़ी चुनौती होगी। वैसे बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, लिहाजा यह भी माना जा सकता है कि उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है।

बीजेपी के जानकारों का तर्क है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय भूमिका देकर पार्टी ने एक तरह से पीढ़ीगत बदलाव की शुरूआत की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों मेंम बीजेपी में और भी युवा चेहरों को मौका मिलेगा। वैसे देखा जाए तो आजकल बीजेपी में युवाओं और महिलाओं पर जोर है। हालिया बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी एमवाई का नया विश्लेषण युवा और महिला के रूप में कर ही चुके हैं। वैसे भी वे गरीब, किसान, महिला और जवान की जाति का अक्सर जिक्र करते हैं। कह सकते हैं कि नितिन नवीन भाजपा की इसी नई वर्ग व्यवस्था के सशक्त प्रतीक हैं।

हाल के दिनों में बीजेपी में पिछड़ा नेतृत्व पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया। इससे बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक दबे स्वर से नाराजगी भी जाहिर करता रहा है। विराट उभार से पहले बीजेपी को बाभन-बनिया की पार्टी भी कहा जाता था। इसमें कायस्थ और किंचित क्षत्रिय वर्ग भी जुड़ा हुआ था। नितिन नवीन इन्हीं में से एक कायस्थ वर्ग से आते हैं। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पाटलिपुत्र से कायस्थ उम्मीदवार ना देने की वजह से बीजेपी का कायस्थ वोटर किंचित नाराज भी दिखा था। इस संदर्भ को देखते हुए एक वर्ग कह रहा है कि नितिन को केंद्रीय नेतृत्व सौंपकर बीजेपी ने अपने पारंपरिक सवर्ण मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश की है। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नितिन नवीन की ताजपोशी आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव को भी ध्यान में रखकर किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक कायस्थ समाज का दबदबा रहा है। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु और पहले मुख्यमंत्री विधानचंद्र रॉय इसी समुदाय से थे। ज्योति बसु जहां 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वहीं विधानचंद्र रॉय के हाथ 14 साल तक राज्य की कमान रही। नितिन नवीन के जरिए बंगाल के इस वर्ग के वोटरों को भी पार्टी ने बड़ा संदेश दिया है।

नितिन नवीन को नेतृत्व सौंपे जाने को लेकर कुछ महीने पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा को मिले संकेतों का भी जिक्र किया जा रहा है। संघ ने बीजेपी को संकेत दिया था कि पिछड़े-दलित आदि को शासन और प्रशासन से मिले फायदों का जिक्र भले ही करे, लेकिन संगठन के मामलों में जातीय आधार पर फैसले ना ले। संघ का पार्टी को यह भी संकेत था कि वह संगठन की भूमिकाएं तय करते वक्त कार्यकर्ताभाव और उसकी संगठन क्षमता और निष्ठा को देखे। नितिन नवीन की नियुक्ति को इस निकष पर भी कसा जा सकता है। नवीन पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे हैं। संगठन ने जो भी भूमिका सौंपी, उसे संगठन के लिहाज से पूरा करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की पिछली जीत ने उनके संगठन कौशल की ओर झांकने का मौका दिया। कह सकते हैं कि उनकी नियुक्ति के पीछे ये भी कारण रहे होंगे। हालांकि आलोचक कह सकते हैं कि नितिन की तुलना में संगठन में खुद को खपाने वाले बहुत लोग अब भी सक्रिय हैं। फिर उन्हें क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। यह तर्क वाजिब हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक फैसले लेते वक्त कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है।

बीजेपी अक्सर दावा करती है कि वह पढ़े-लिखे लोगों को तवज्जो देती है। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं की उनकी आक्रामक और बदतमीज व्यवहार के चलते आलोचना की थी। तब उसने अपने पढ़े-लिखे प्रवक्ताओं पर जोर दिया था। इस आधार पर नितिन नवीन को लेकर बीजेपी असहज हो सकती है। विपक्षी कह सकते हैं कि पार्टी को अपने अध्यक्ष के लिए पढ़ा-लिखा कार्यकर्ता नहीं मिला। क्योंकि नितिन महज बारहवीं पास ही हैं। बीजेपी अक्सर वंशवाद का विरोध करती है। तकरीबन हर मंच पर वह इसके खिलाफ आवाज उठाती है। जब पार्टी के अंदर के वंशवाद पर विपक्षी खेमे से सवाल उठता रहा, तब पार्टी का तर्क होता था कि शीर्ष पर उसके यहां वंशवाद नहीं रहा। नितिन के संदर्भ में वह क्या जवाब देगी, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि नितिन के पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। बिहार में बीजेपी को खड़ा करने वाले नेताओं में नवीन किशोर का योगदान माना जाता रहा है। आखिर में एक और तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। 1959 में जब दिग्गज नेताओं के रहते हुए भी कांग्रेस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाया, तब इंदिरा की उम्र महज 42 साल थी। ठीक 66 साल बाद आज की सत्ताधारी बीजेपी ने पैंतालिस साल के नितिन नवीन पर भरोसा जताया है। अध्यक्ष बनने के सिर्फ छह साल बाद ही वे देश की प्रधानमंत्री बन गई थीं, नितिन आगे और कितनी ऊंचाई पर जाएंगे, यह देखने के लिए इंतजार करना होगा।

प्रेरणा

करुणा की डोर से बंधी भटकी ज़िंदगी

जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों के बीच बनी एक छोटी-सी झोपड़ी के पास एक गड़रिया अपनी दिनभर की थकान भूल चुका था। उसके कंधों पर एक कमजोर-सी भेड़ टिकी थी, जिसकी आँखों में डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। गड़रिया उसे बहुत संभलकर नीचे उतारता है, मानो कोई अनमोल धरोहर हो। वह पास की नदी से पानी लाता है, भेड़ को नहलाता है और अपने हाथों से उसके शरीर से जंगल की धूल, काँटे और भय को धो देता है। फिर धूप में बैठाकर उसके गीले ऊन को सुखाता है। इस पूरे समय उसके चेहरे पर झुंझलाहट नहीं, बल्कि अपनापन और धैर्य झलकता है।

जब भेड़ हरी घास खाने लगती है, तो गड़रिए के मन में एक अजीब-सी तृप्ति भर जाती है। यह वही भेड़ थी जो बार-बार झुंड से अलग हो जाती थी, जो हर बार जंगल के अँधेरे रास्तों में भटक जाती थी। कई बार गड़रिए को रात-रात भर उसे ढूँढना पड़ा था। बाकी भेड़ें सीधी राह जानती थीं, लेकिन यह डर के कारण रास्ता भूल जाती थी। फिर भी गड़रिए ने कभी इसे त्यागने का विचार नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह भी उतनी ही अपनी थी जितनी बाकी सभी।

उसी झोपड़ी के पास महापुरुष ईसा कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। उनकी दृष्टि गड़रिए और भेड़ पर पड़ी तो वे रुक गए। उन्होंने उस दृश्य में एक गहरी सीख देखी। ईसा ने गड़रिए से पूछा, “वत्स, इतनी सेवा और स्नेह इस एक भेड़ के लिए क्यों? जब तुम्हारे पास और भी कई भेड़ें हैं जो स्वयं लौट आती हैं।”

गड़रिए ने नम्र स्वर में कहा, “महात्मन, यही भेड़ सबसे अधिक भटकती है। अगर इसे डाँटूँ या छोड़ दूँ तो यह और दूर चली जाएगी। मैंने इसे प्रेम इसलिए दिया ताकि इसके मन से भय मिट जाए और इसे यह विश्वास हो जाए कि इसका भी कोई अपना है।”

ईसा के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा कि यही तो जीवन का सत्य है। जो सबसे अधिक भटकते हैं, जो सबसे अधिक गलतियाँ करते हैं, वही सबसे अधिक प्रेम के अधिकारी होते हैं। मनुष्य भी इसी भेड़ की तरह है। जब वह जीवन के जंगल में रास्ता भूल जाता है, तब उसे उपदेशों से अधिक स्नेह की आवश्यकता होती है। कठोरता उसे और दूर ले जाती है, जबकि करुणा उसे वापस खींच लाती है।

ईसा ने आगे कहा कि ईश्वर भी मनुष्य को इसी तरह खोजता है। वह भटके हुए को त्यागता नहीं, बल्कि अपने कंधों पर उठाकर घर लौटाता है। जैसे इस गड़रिए ने अपनी भेड़ को अपनाया, वैसे ही हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए गड़रिया बनना चाहिए। उस शाम जंगल के सन्नाटे में यह बात गूँजती रही कि संसार को सुधारने का सबसे सशक्त उपाय दंड नहीं, बल्कि प्रेम है। भटकी हुई ज़िंदगी को सही राह पर लाने के लिए करुणा की डोर ही सबसे मज़बूत होती है।

भारत चुपचाप कर रहा बड़ी तैयारी, मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा विरोधियों पर पड़ रही भारी

युद्ध के धुएँ और वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में भारत की विदेश नीति अगर किसी एक शब्द में परिभाषित होती है, तो वह है रणनीतिक स्पष्टता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा इसी स्पष्टता का ठोस प्रदर्शन है। यह यात्रा बदलती वैश्विक ध्रुवीयता में भारत के हितों को सुरक्षित करने की एक सधी हुई चाल है। यह एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा, खाद्य, समुद्री और भू-राजनीतिक सुरक्षा की रीढ़ बनेगा। देखा जाये तो पश्चिम एशिया इस समय उबाल पर है। गाज़ा संकट, ईरान-सऊदी समीकरणों में उतार-चढ़ाव, अमेरिका की प्राथमिकताओं में बदलाव और सऊदी अरब-पाकिस्तान और अमेरिका के नए रक्षा समीकरण का उभरना भारी उथलपुथल की तरह है। ऐसे में भारत का जॉर्डन और ओमान की ओर बढ़ना बताता है कि नई दिल्ली अब प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि एजेंडा-सेटर है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी एक धुरी पर निर्भर नहीं रहेगा, वह अपने विकल्प खुद गढ़ेगा।

मोदी के तीन देशों के दौरे में जॉर्डन पहला पड़ाव था और यह चयन ही बहुत कुछ कह देता है। हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जॉर्डन एक संतुलनकारी शक्ति है। वह कट्टरपंथ के विरुद्ध ढाल और संवाद का सेतु है। भारत के लिए जॉर्डन केवल कूटनीतिक मित्र नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा का रणनीतिक स्तंभ भी है। फॉस्फेट और पोटाश जैसे उर्वरकों के बिना भारत की कृषि का आगे बढ़ना मुश्किल है। जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइज़र कंपनी (JIFCO) जैसे उपक्रम इस बात का प्रमाण हैं कि मोदी सरकार संसाधन सुरक्षा को भाषण नहीं, संस्थागत रणनीति मानती है। दोनों देशों के बीच $2.75 अरब का द्विपक्षीय व्यापार और 2030 तक $5 अरब का लक्ष्य दिखाता है कि यह साझेदारी अब प्रतीकात्मक नहीं रही। मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान हुए करार और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को वहां की सरकार का मिला जोरदार समर्थन तथा क्राउन प्रिंस का खुद मोदी को अपनी कार में लेकर जाना दर्शाता है कि मोदी की यात्रा कितनी सफल रही। वहीं मोदी की इथियोपिया यात्रा को देखें तो यह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत निर्णायक है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय, ब्रिक्स का सदस्य और ग्लोबल साउथ की धड़कन, इथियोपिया में 2011 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। देखा जाये तो यह देरी नहीं, बल्कि सही समय पर किया गया दांव है। दोनों देशों के बीच $550 मिलियन का व्यापार, भारतीय फार्मा की मजबूत मौजूदगी और क्षमता निर्माण में भारत की भूमिका दिखाती है कि नई दिल्ली अफ्रीका को बड़ा साझेदार मानती है। यह चीन के ऋण-जाल मॉडल के ठीक उलट सम्मान, प्रशिक्षण और साझा विकास का रास्ता है।

साथ ही मोदी की ओमान यात्रा भारत की समुद्री रणनीति का निर्णायक स्तंभ है। दुक्म (Duqm) बंदरगाह में भारत की बढ़ती मौजूदगी, होरमुज़ जलडमरूमध्य से बाहर एक वैकल्पिक लॉजिस्टिक हब, यह सब भारत की इंडो-लिटरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत-ओमान CEPA का प्रस्तावित हस्ताक्षर इस यात्रा का सबसे ठोस आर्थिक परिणाम होगा। देखा जाये तो 95% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच और 98% तक भारतीय वस्तुओं को राहत, एक रणनीतिक व्यापार की तरह है। ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, उर्वरक, तकनीक और खाद्य सुरक्षा, हर मोर्चे पर भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच $10.61 अरब का व्यापार जल्द ही $20 अरब की ओर बढ़े, यह केवल आंकड़ा नहीं, भरोसे की मुद्रा है।

हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरी यात्रा की बेहद शक्तिशाली धुरी हैं भारतीय प्रवासी। ओमान में 6.75 लाख से अधिक भारतीय, जॉर्डन में परिधान उद्योग की रीढ़ बने 17 हजार श्रमिक और इथियोपिया में शिक्षा जगत को दिशा देने वाले भारतीय प्रोफेसर, ये लोग भारत की “सॉफ्ट पावर” नहीं, बल्कि लिविंग स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। मोदी सरकार ने पहली बार प्रवासियों को भावनात्मक प्रतीक से निकालकर नीति के केंद्र में रखा है, चाहे वह बिज़नेस कार्ड वीज़ा हो या श्रम सुरक्षा के समझौते।

बहरहाल, आलोचक कह सकते हैं कि यह यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है क्योंकि पश्चिम एशिया की अस्थिरता, अफ्रीका में प्रतिस्पर्धा और वैश्विक आर्थिक सुस्ती बनी हुई है। लेकिन यहीं मोदी सरकार की विदेश नीति अलग दिखती है। यह जोखिम से भागती नहीं, उसे मैनेज करती है। मोदी सरकार जानती है कि बहुध्रुवीय विश्व में निष्क्रियता सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए निष्कर्ष स्पष्ट है। मोदी की यह यात्रा भारत के आत्मविश्वास का बयान है कि भारत अब केवल संतुलन साधने वाला देश नहीं, बल्कि अपने हितों के लिए गठबंधन गढ़ने वाला राष्ट्र है। मोदी की यह पश्चिम एशिया-अफ्रीका कूटनीति लेन-देन से आगे जाकर रणनीतिक हेजिंग की परिपक्व मिसाल है। आने वाले वर्षों में जब ऊर्जा, खाद्य और समुद्री मार्गों पर संघर्ष तेज होगा, तब यह यात्रा एक दूरदर्शी कदम के रूप में याद की जाएगी, जिसने भारत को न केवल सुरक्षित किया, बल्कि निर्णायक भी बनाया।

अभियान

साधना से सिद्धि तक की पावन तिथि

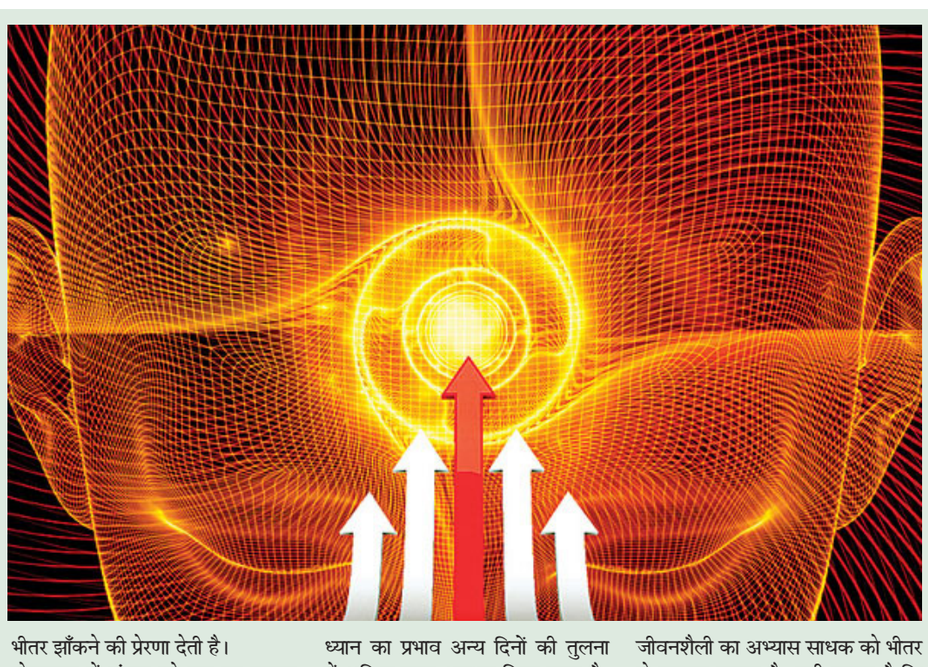

सनातन संस्कृति में समय को केवल बीतने वाला क्षण नहीं माना गया, बल्कि उसे चेतना से जुड़ा अवसर माना गया है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी भी ऐसा ही एक अवसर है, जब साधक का मन सहज रूप से भक्ति, संयम और आत्मिक शुद्धि की ओर उन्मुख हो जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु की उपासना को समर्पित है, पर इसका प्रभाव केवल मंदिर या पूजा-स्थान तक सीमित नहीं रहता। यह एकादशी मनुष्य के आचरण, उसकी इच्छाओं और उसके जीवन-व्यवहार को भीतर से अनुशासित करने का अवसर देती है।

भारतीय जीवन पद्धति में एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और विचारों की स्वच्छता का अभ्यास है। वर्ष भर में आने वाली चौबीस एकादशियों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। लोकमान्यता के अनुसार इस व्रत से जीवन के विघ्न दूर होते हैं और साधक की मनोकामनाएँ सफल होती हैं। ‘सफला’ शब्द अपने आप में संकेत करता है कि यह तिथि जीवन को सही दिशा और सार्थकता देने वाली है। इस दिन की साधना मन को स्थिर करती है और व्यक्ति को अपने भीतर झाँकने की प्रेरणा देती है।

योगशास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और एकादशी तिथि को मन को शांत करने के लिए अत्यंत अनुकूल कहा गया है। इस दिन उपवास, जप और ध्यान का प्रभाव अन्य दिनों की तुलना में अधिक गहरा अनुभव किया जाता है। जब भोजन का संयम होता है, तो विचार स्वतः हल्के और निर्मल होने लगते हैं। तामसिक आहार का त्याग और सात्त्विक जीवनशैली का अभ्यास साधक को भीतर से सशक्त बनाता है। यही कारण है कि एकादशी को सिद्धि-दायिनी तिथि कहा गया है।

सफला एकादशी का महत्व केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक स्वरूप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दिन दान-पुण्य की परंपरा भारतीय समाज में करुणा और सेवा की भावना को प्रबल करती है। अन्न, फल, वस्त्र और आवश्यक वस्तुओं का दान समाज के कमजोर वर्गों तक संवेदना पहुँचाने का माध्यम बनता है। भजन, कीर्तन और सत्संग के माध्यम से लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं और सामूहिक चेतना का अनुभव करते हैं। किसान और व्यापारी इस तिथि को नए संकल्प और शुभ आरंभ का प्रतीक मानते हैं।

सफला एकादशी से जुड़ी कथा इस व्रत के मर्म को अत्यंत सरल और गहन रूप में प्रकट करती है। राजा महिषमति का पुत्र लुबंक अपने दुराचरण और अनुशासनहीनता के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। जंगल में भटकते हुए उसका जीवन अपराध और पतन की ओर बढ़ता चला गया। एक दिन भीषण ठंड में, भूख और असहाय अवस्था में, वह एक वृक्ष के नीचे बैठा रहा। उसके पास न भोजन था, न कोई आश्रय। अनजाने में उसने एकादशी का पूर्ण उपवास कर लिया। अगले दिन जो थोड़े-से फल उसे मिले, उन्हें उसने वृक्ष के नीचे रख दिया और विश्राम करने लगा। उसकी यह सरल, निष्कपट और अहंकाररहित अवस्था भगवान विष्णु को स्वीकार्य हो गई। इस अनजाने व्रत और निष्कलंक भाव का प्रभाव लुबंक के जीवन में गहरे परिवर्तन के रूप में प्रकट हुआ। उसके भीतर पश्चाताप जागा, मन शुद्ध हुआ और आचरण बदलने लगा। अंततः वह अपने पूर्व कर्मों से मुक्त होकर पुनः राज्य में लौटा और एक योग्य शासक बना। यह कथा बताती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए दिखावा या जटिल कर्मकांड आवश्यक नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्चा भाव ही पर्याप्त है।

सफला एकादशी का संदेश यही है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप आचरण की पवित्रता में प्रकट होता है। यह तिथि मनुष्य को यह समझाती है कि संयम, सच्चाई और करुणा ही अध्यात्म की सच्ची पहचान हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है और जीवन को अनुशासित करता है, तभी साधना सफल होती है। इसी अर्थ में सफला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, शांत और सफल बनाने की पावन साधना है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात की राष्ट्रीय उपलब्धि

- ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत गांधीनगर के जीवराजना मुवाड़ा प्राथमिक स्कूल को मिला राष्ट्रीय स्तर का ‘ग्रीन स्कूल अवॉर्ड-2025’
- देशभर के 720 स्कूलों में से गुजरात के सरकारी प्राथमिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया
- मुंबई में आयोजित ‘इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस’ में अवॉर्ड दिया गया
- ग्रीन स्कूल से जुड़े 11 नए विचारों-प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए विशेष सम्मान
- विभिन्न प्रकार के लगभग 1,200 से अधिक वृक्षों से स्कूल का ग्रीन कैंपस सुसज्जित

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गांधीनगर जिले के जीवराजना मुवाडा गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में केवल जिले का ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का गौरव बढ़ाया है। मुंबई में इन्डियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत गांधीनगर के जीवराजना मुवाडा प्राथमिक स्कूल को राष्ट्रीय स्तर का ‘ग्रीन स्कूल अवॉर्ड-2025’ दिया है। लगभग 1,200 से अधिक वृक्षों वाले इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन स्कूल से संबंधित 11 नए विचारों तथा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए 3 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है।

केंद्र सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तथा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संयुक्त उपक्रम से नवंबर-2025 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किया गया। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा हर वर्ष ‘ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम’ के अंतर्गत देश भर से स्कूलों के पंजीकरण आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें इस वर्ष देश से 720 स्कूलों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की थी, जिनमें से प्रथम तीन स्थान पर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी के स्कूलों का चयन किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर, 2025 को गुजरात सहित तीन स्कूलों द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूशन, मुंबई में जूरी के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्य के समग्र शिक्षा विभाग, स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बिपिन गोस्वामी तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किए गए ग्रीन स्कूल से संबंधित 11 नए विचारों और स्कूल में चल रहे प्रोजेक्ट पर देहगाम तहसील के जीवराजना मुवाड़ा प्राथमिक स्कूल के छात्रों; श्री मीत ठाकोर, श्री यामी ठाकोर और श्री जिग्नेश झाला द्वारा जूरी के समक्ष प्रभावी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

इस ग्रीन अवॉर्ड के लिए स्कूल द्वारा कुल 11 आईडिया दिए गए थे, जिनमें होम मेड जीवामृत, पेपर रिसाइक्लिंग, मूड पेंटिंग, अर्थन पॉट एसी विद होममेड, पोर्टेबल बायोगैस प्लांट, प्लास्टिक फ्री स्कूल, स्मार्ट एनर्जी ऑडिट, ग्रे वाटर सिस्टम, सोलर वोटर पंप, नेकी की दीवार, रेड बुक डेटा जैसे विचार शामिल हैं, जिनका आगामी समय में क्रियान्वयन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त स्कूल में ऊर्जा, पानी तथा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल में ‘फ्री प्लास्टिक स्कूल, फ्री प्लास्टिक विलेज’ पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 में क्लाइमेट चेंज का अवॉर्ड भी इस स्कूल को प्रदान किया गया था। बच्चे स्कूल में चॉकलेट की जगह छोटा पौधा भेंट करते हैं और जब तक वे पढ़ते हैं, तब तक उसका संरक्षण भी स्कूल के बच्चों द्वारा किया जाता हैं। स्कूल में विभिन्न वेस्ट वस्तुओं से फाइटर प्लेन, सैटेलाइट, पवन चक्की, पृथ्वी का गोलाकार मॉडल (ग्लोब), हाइड्रोपोनिक सिस्टम जैसे अनेक नवीन मॉडल बनाए गए हैं। इसके साथ ही बटरफ्लाई गार्डन की देखभाल तथा किचन गार्डन जैसी सर्जनात्मक प्रवृतियां कर छोटे छात्रों ने शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

किसान संगठन के अग्रणियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात

किसान हितैषी दृष्टिकोण के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में हुई बेमौसम और असाधारण बारिश की स्थिति में किसानों के साथ खड़े रहकर 10 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने वाले प्रभावित किसानों को अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 5300 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस किसान हितकारी दृष्टिकोण के लिए राज्य की विभिन्न खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समितियों (एपीएमसी), मार्केट यार्ड और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को गांधनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इतना ही नहीं, मूंगफली सहित विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी कर राज्य सरकार किसानों हिमायती बनी है।

ऐसे किसान हितैषी कदमों और त्वरित निर्णयों से किसी भी आपदा की घड़ी में धरतीपुत्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य सरकार सदैव संवेदनशील रही है, इसके लिए भी किसान अग्रणियों ने राज्य के किसानों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, मंत्री सर्वश्री ऋषिकेशभाई पटेल, कुंवरजीभाई बावळिया, नरेशभाई पटेल, अर्जुनभाई मोढवाडिया और डॉ. प्रद्युमन वाजा भी उपस्थित रहे।

आणंद - गोधरा सेक्शन पर स्पीड बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा की गयी

(जीएनएस)।वडोदरा मंडल द्वारा आणंद -गोधरा सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत स्पीड को सफलतापूर्वक बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है। इससे रेल खंड की सेक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और समय की बचत होने से यात्रियों का सफ़र अधिक आरामदायक होगा।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आणंद -गोधरा सेक्शन की कुल लंबाई 78 किलोमीटर है। सेक्शन पर यात्री यातायात शुरु होने पर अप लाइन पर स्पीड लिमिट लगाई गई थी। सेक्शन में स्पीड अपग्रेडेशन करने के लिए बैलास्ट प्रोफाइल में व्यवस्थित सुधार किया गया और साथ ही कुछ पुलों को और मजबूत किया गया। यह पहल वडोदरा मंडल की आधुनिक रखरखाव तरीकों को अपनाने और बेहतर परिचालन दक्षता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्पीड अपग्रेडेशन से यात्रियों को इस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर पर यात्रा के समय में कमी, ट्रेनों के सुचारू संचालन और सेवाओं की बेहतर विश्वसनीयता का लाभ मिलेगा। वडोदरा मंडल यात्रिओं को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक रेल सेवाएं प्रदान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण और सुरक्षा-उन्मुख कार्यों को जारी रखने के लिए प्रतिबध्द है।

पश्चिम रेलवे वलसाड एवं वेलांकन्नि के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से वलसाड एवं वेलांकन्नि स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09047/09048 वलसाड – वेलांकन्नि स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09047 वलसाड–वेलांकन्नि स्पेशल वलसाड से शनिवार, 20 दिसंबर, 2025 को 17.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा सोमवार को 07.30 बजे वेलांकन्नि पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09048 वेलांकन्नि – वलसाड स्पेशल वेलांकन्नि से सोमवार, 22 दिसंबर, 2025 को 22.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा बुधवार 13.30 बजे वलसाड पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वापी, वसई रोड, कल्याण, लोनावला, पुणे, सोलापुर, कलबुरगि, वाडी, यादगिर, कृष्णा, रायचूर, मंत्रालयम रोड, अदोनि, गुंतकल, गूटी, ताडिपत्रि, यर्रगुंटला, कडप्पा, राजमपेटा, रेणिगुंटा, काटपाडी, तिरुवण्णामलै, विल्लुपुरम, कडलूर पोर्ट, चिदम्बरम, मयिलादुतुरै, कारैक्काल, नागूर और नागप्पट्टिनम स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09047 की बुकिंग 18 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल आज मनपाओं और नपाओं को 2800 करोड़ रुपए की ग्रांट-सहायता राशि के चेक वितरित करेंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल कल यानी बुधवार, 17 दिसंबर, 2025 को दोपहर 3.00 बजे अहमदाबाद में राज्य की महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए की राशि के चेक वितरित करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2025 का वर्ष शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तब 2800 करोड़ रुपए की ग्रांट-सहायता की यह राशि राज्य के शहरी विकास को नई गति देगी।

अहमदाबाद के शैला इलाके में स्थित औडा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शहरी विकास मंत्री श्री कनुभाई देसाई, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला और महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के पदाधिकारी भी मौजूद

विकसित बिहार की दिशा में बड़ा कदमः नीतीश कैबिनेट से ‘सात निश्चय-3’ को हरी झंडी, रोजगार से निवेश तक बदलेगा राज्य का चेहरा

(जीएनएस)। पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी विकास योजना ‘सात निश्चय-3’ को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि इस योजना का मूल उद्देश्य अगले पांच वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही यह साफ हो गया है कि सरकार अब विकास, रोजगार और निवेश को केंद्र में रखकर बड़े स्तर पर नीतिगत और संरचनात्मक बदलाव करने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद बताया कि सात निश्चय-3 के तहत युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की योजनाओं को भी व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

सरकार ने औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने की रूपरेखा भी तैयार की है। सात निश्चय-3 के तहत करीब 50 लाख करोड़ रुपये तक के निजी निवेश को बिहार में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाने, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और निवेशकों को अनुकूल माहौल देने पर जोर दिया जाएगा। नई एक्सप्रेस-वे सड़कों के निर्माण और परिवहन नेटवर्क के विस्तार से राज्य के भीतर और बाहर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना भी इसमें शामिल है।

कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है। कृषि रोड मैप को नई गति दी जाएगी, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसके साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ करने की योजना भी सात निश्चय-3 का अहम हिस्सा है।

घने कोहरे में तेज रफ्तार का कहर: यूपी में 31 की मौत, यमुना एक्सप्रेसवे पर 13 लोग जिंदा जले

यमुना एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराईं गाड़ियों में लगी आग से जिंदा जले यात्री, पहचान भी मुश्किल, डीएनए टेस्ट की तैयारी, हेल्पलाइन नंबर जारी

(जीएनएस)। मथुरा/उन्नाव/बस्ती/बागपत/बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और तेज रफ्तार का कहर मंगलवार को जानलेवा साबित हुआ। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार दिनभर तक राज्य के अलग-अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में कुल 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 87 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे भयावह हादसा मथुरा जिले के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां वाहनों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग में 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कई शव इतनी बुरी तरह झुलस गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है।

मथुरा जिले के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के 127 किलोमीटर माइलस्टोन के पास मंगलवार तड़के घना कोहरा छाया हुआ था। इसी दौरान तेज रफ्तार कई वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते सात बसों और तीन कारों में आग लग गई। आग की लपटों में फंसे यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और 13 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मथुरा और वृंदावन के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भीषण आग के कारण कई शव पूरी तरह जल चुके हैं, जिससे उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल केवल कुछ ही शवों की पहचान हो सकी है। मथुरा जिला प्रशासन ने हादसे से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0565-2403200 जारी किया है। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा के मोबाइल नंबर 9454417583 और एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत के मोबाइल नंबर 9454401103 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

कोहरे का कहर यहीं नहीं रुका। उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक कार का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गाजियाबाद निवासी अशोक अग्रवाल (57), आकाश अग्रवाल (35) और अभिनव अग्रवाल (20) के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

बस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जिनमें बस्ती निवासी अब्दुल्ला (60), मुख्तार अली (75), बस चालक संदीप पांडेय (32) और ट्रक चालक शिवराज सिंह शामिल हैं। हादसे में 10 अन्य यात्री घायल हुए हैं। बताया गया कि संतकबीर नगर से एक निजी बस यात्रियों को लेकर अजमेर शरीफ उर्स में शामिल होने जा रही थी, तभी कोतवाली क्षेत्र के हरदिया के पास यह दुर्घटना हो गई।

बागपत जिले में भी कोहरे ने दो जिंदगियां ले लीं। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में रात करीब दो बजे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में हेड कांस्टेबल राहुल और अजहरुद्दीन की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कांस्टेबल सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा है।

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान बिहार के छपरा निवासी बबलू (35) और आजमगढ़ के लालगंज निवासी दीपक कुमार (36) के रूप में हुई है।

राजधानी लखनऊ में भी सड़क हादसों ने जान ली। रहीमाबाद थाना क्षेत्र में लखनऊ-हरदोई रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार प्रिंस यादव की मौत हो गई, जबकि अरुण घायल हो गया। वहीं, महिगवा थाना क्षेत्र में एक अन्य हादसे में बाइक सवार रामनाथ उर्फ कोटे की जान चली गई।

इसके अलावा सोनभद्र जिले में खड़ी पिकअप में पीछे से कार की टक्कर से ओरियंटल इंश्योरेंस के शाखा प्रबंधक सत्य प्रकाश गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ में जेसीबी और बाइक की टक्कर में बबलू गौतम की मौत हो गई, जबकि राजू गौतम गंभीर रूप से घायल है। मीरजापुर में 80 वर्षीय बुजुर्ग बल्लू यादव सड़क हादसे में जान गंवा बैठे। नोएडा में सेक्टर-113 क्षेत्र के सोरखा गांव के पास चलती कार में आग लगने से पेंट व्यवसायी राजकुमार सिंघल (46) की जिंदा जलकर मौत हो गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी सड़क हादसों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कई मामलों में मुआवजे की घोषणा की है और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

लगातार हो रहे इन हादसों ने एक बार फिर कोहरे में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है। प्रशासन की अपील के बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है।

माननीय विधायक श्री लक्ष्मणजी ठाकोर ने कलोल स्टेशन पर चार ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ किया

(जीएनएस)। माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में माननीय विधायक श्री लक्ष्मणजी पुंजाजी ठाकोर ने 16 दिसंबर 2025 को कलोल रेलवे स्टेशन पर वलसाड–वडनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर माननीय विधायक, कलोल श्री लक्ष्मणजी ठाकोर ने अपने संबोधन में कहा कि कलोल रेलवे स्टेशन पर

1. 20959/60 वलसाड–वडनगर–वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कलोल को वलसाड, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद तथा वडनगर जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है।
2. 16507/08 जोधपुर–बेंगलुरु–जोधपुर एक्सप्रेस, जो कलोल को राजस्थान, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ती है।
3. 15269/70 मुजफ्फरपुर–साबरमती–मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कलोल को बिहार सहित उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ती है और आम यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
4. 12215/16 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीबरथ एक्सप्रेस, जो कलोल को देश की राजधानी दिल्ली तथा आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जोड़ती है।

इन सभी ट्रेनों के ठहराव से कलोल एवं आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी, सुलभ और समय की बचत करने वाली यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। GIDC छत्राल में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी तथा उनको ट्रेन पकड़ने के लिए महेसाणा और अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही विद्यार्थियों, नौकरीपेशा वर्ग, व्यापारियों, किसानों तथा स्थानीय श्रमिकों को अन्य बड़े स्टेशनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा में होने वाला समय, श्रम और आर्थिक व्यय—तीनों में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

कलोल रेलवे स्टेशन का लगभग 44.22 करोड़ रु. की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कलोल स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है।

कलोल स्टेशन पर 40 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों को जोड़ते हुए शहर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही, स्टेशन के पूर्वी छोर पर द्वितीय प्रवेश (सेकेंड एंट्री) भवन का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे कलोल के पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों को टिकट बुकिंग, प्रतीक्षालय एवं अन्य यात्री सुविधाओं का सीधा लाभ प्राप्त होगा।

वर्तमान में कलोल स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 2,000 यात्री आवागमन करते हैं और 24 ट्रेनें यहां नियमित रूप से रुकती हैं। हैं। इन चार जोड़ी ट्रेनों के ठहराव के साथ कुल 32 ट्रेनों का ठहराव कलोल स्टेशन पर हो जाएगा।

इन चार ट्रेनों का कलोल स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान का समय निम्नानुसार रहेगा:

1. ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड–वडनगर-वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20959 वलसाड–वडनगर एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 11.37 बजे आगमन एवं 11.39 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20960 वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.15 बजे आगमन एवं 18.17 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन संख्या 12215/12216 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 22.41 बजे आगमन एवं 22.43 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस 16 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 20.11 बजे आगमन एवं 20.13 बजे प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन संख्या 16507/16508 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16507 जोधपुर–केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 12.55 बजे आगमन एवं 12.57 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 16508 केएसआर बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस 17 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 06.19 बजे आगमन एवं 06.21 बजे प्रस्थान करेगी।

4. ट्रेन संख्या 15269/15270 मुजफ्फरपुर–साबरमती साप्ताहिक जनसाधारण एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 15269 मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 05.53 बजे आगमन एवं 05.55 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस 20 दिसंबर 2025 से कलोल स्टेशन पर 18.28 बजे आगमन एवं 18.30 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा हेतु कुछ ट्रेनों के समय में संशोधन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं ट्रेनों की समयपालन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से संबंधित कुछ ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह संशोधित समयसारणी 22 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी।

प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

1. ट्रेन संख्या 59561 राजकोट–पोरबंदर के राजकोट से प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है तथा मार्ग के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन/प्रस्थान समय संशोधित किए गए हैं। पोरबंदर पर आगमन समय पूर्ववत रहेगा। यह ट्रेन राजकोट से 08.35 बजे की बजाय 08.50 बजे प्रस्थान करेगी।
2. ट्रेन संख्या 59422 वेरावल–राजकोट के वेरावल से रीबडा स्टेशन तक समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। इस ट्रेन का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः 09.17/09.18 बजे की बजाय 09.04/09.06 बजे रहेगा।
3. ट्रेन संख्या 19207 पोरबंदर–राजकोट के वेरावल से गोंडल तक समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भक्तिनगर स्टेशन पर समय संशोधित किया गया है। इस ट्रेन का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः 08.12/08.14 बजे की बजाय 08.07/08.09 बजे रहेगा।
4. ट्रेन संख्या 59423 राजकोट–वेरावल के राजकोट से प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है तथा भक्तिनगर स्टेशन पर संशोधित समय लागू होगा। आगे वेरावल तक समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह ट्रेन राजकोट से 08.00 बजे की बजाय 07.55 बजे प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का भक्तिनगर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः 08.12/08.14 बजे की बजाय 08.07/08.09 बजे रहेगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेन का संशोधित समय रेलवे पूछताछ, अधिकृत रेलवे वेबसाइट अथवा निकटतम रेलवे स्टेशन से अवश्य जांच लें।

भारत के एआई और हेल्थ सेक्टर में बड़ा निवेश: गूगल देगा 8.4 मिलियन डॉलर, स्वदेशी मॉडल और भाषाई तकनीक को मिलेगी मजबूती

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने देश में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने और स्वास्थ्य मॉडल के विकास को गति देने के लिए कुल 8.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस निवेश का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और टिकाऊ शहरों से जुड़े एआई उत्कृष्टता केंद्रों के विकास के साथ-साथ भारत-विशिष्ट स्वास्थ्य समाधान तैयार करने में किया जाएगा। गूगल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कंपनी भारत में बहुभाषी और समावेशी एआई तकनीक को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि तकनीकी प्रगति का लाभ देश के हर वर्ग और हर भाषा तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य के तहत स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में एआई आधारित अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए वधवानी एआई को 45 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय भाषाओं पर केंद्रित एआई समाधान तैयार करने के लिए ज्ञानीडॉटएआई, कोरोवरडॉटएआई और भारतजेन को 50-50 हजार अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर गूगल का फोकस खास तौर पर भारत की जरूरतों के अनुरूप एआई मॉडल तैयार करने पर है। कंपनी ने भारत के स्वास्थ्य मॉडल के विकास में सहयोग के लिए चार लाख अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस पहल के तहत 'मेडगेम्मा' तकनीक का उपयोग करते हुए नए सहयोग शुरू किए जाएंगे। अजना लेंस और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञ मिलकर त्वचा रोग विज्ञान और ओपीडी ट्राइएजिंग के लिए भारत-विशिष्ट एआई मॉडल विकसित करेंगे, जिससे मरीजों की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और इलाज की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के शोधकर्ता और चिकित्सक एआई के व्यापक नैदानिक उपयोग की संभावनाओं पर काम करेंगे, ताकि तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार हो सके।

गूगल ने भारतीय भाषाओं और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मुंबई को भी बड़ी सहायता देने की घोषणा की है। कंपनी आईआईटी मुंबई में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक योगदान देगी। गूगल का कहना है कि इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एआई में हो रही वैश्विक प्रगति भारत की भाषाई विविधता के अनुरूप हो और देश के सामाजिक व आर्थिक हितों को मजबूती मिले।

विशेषज्ञों का मानना है कि गूगल का यह निवेश भारत में एआई आधारित नवाचारों को नई गति देगा। खासकर स्वास्थ्य और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में यह पहल देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती है। सरकार और निजी संस्थानों के सहयोग से विकसित होने वाले ये एआई मॉडल भविष्य में न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं।

एमसीएक्स पर सोना वायदा 582 रुपये और चांदी वायदा 1144 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा 61 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 33400.55 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 189286.14 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 27335.23 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 32590 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 222690.4 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 33400.55 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 189286.14 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 32590 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2280.99 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 27335.23 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 133523 रुपये के भाव पर खूलकर, 134094 रुपये के दिन के उच्च और 133308 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 134130 रुपये के पिछले बंद के सामने 582 रुपये या 0.43 फीसदी की गिरावट के साथ 133548 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 403 रुपये या 0.38 फीसदी लुढ़ककर 106900 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 55 रुपये या 0.41 फीसदी लुढ़ककर 13383 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132350 रुपये के भाव पर खूलकर, 132420 रुपये के दिन के उच्च और 131663 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 571 रुपये या 0.43 फीसदी लुढ़ककर 131920 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 132500 रुपये के भाव पर खूलकर, 132764 रुपये के दिन के उच्च और 132000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132802 रुपये के पिछले बंद के सामने 485 रुपये या 0.37 फीसदी लुढ़ककर 132317 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 195056 रुपये के भाव पर खूलकर, 197708 रुपये के दिन के उच्च और 194260 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 197901 रुपये के पिछले बंद के सामने 1144 रुपये या 0.58 फीसदी लुढ़ककर 196757 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1154 रुपये या 0.58 फीसदी गिरकर 197317 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1118 रुपये या 0.56 फीसदी घटकर 197330 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 3094.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 2 रुपये या 0.18 फीसदी गिरकर 1107.7 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 4 रुपये या 1.3 फीसदी गिरकर 304.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 1.1 रुपये या 0.39 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 281.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 10 पैसे या 0.06 फीसदी के सुधार के साथ 181.35 रुपये प्रति किलो बोला गया। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2998.92 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 5149 रुपये के भाव पर खूलकर, 5154 रुपये के दिन के उच्च और 5074 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 61 रुपये या 1.19 फीसदी गिरकर 5081 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 64 रुपये या 1.24 फीसदी की गिरावट के साथ 5081 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 365.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 365.6 रुपये के दिन के उच्च और 353.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 369.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 12.1 रुपये या 3.27 फीसदी लुढ़ककर 357.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 12.1 रुपये या 3.27 फीसदी गिरकर 357.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 933 रुपये पर खूलकर, 17.1 रुपये या 1.84 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 945.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 12679.33 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 14655.90 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2199.54 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 200.49 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 46.59 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 647.50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 712.72 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2276.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15770 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 72576 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20047 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 329334 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 34694 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16605 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40459 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 115366 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24537 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 41301 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा 32500 पॉइंट पर खूलकर, 32640 के उच्च और 32415 के नीचले स्तर को छूकर, 211 पॉइंट घटकर 32590 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 42.2 रुपये की गिरावट के साथ 30.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.2 रुपये की गिरावट के साथ 13.25 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 225 रुपये की गिरावट के साथ 740 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 845.5 रुपये की गिरावट के साथ 4248.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.3 रुपये की गिरावट के साथ 10.75 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.53 रुपये की गिरावट के साथ 1 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 16.1 रुपये की बढ़त के साथ 46.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.7 रुपये की बढ़त के साथ 15.35 रुपये हुआ।

इसके सामने चांदी दिसंबर 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 100.5 रुपये की बढ़त के साथ 1015 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 56 पैसे के सुधार के साथ 12.72 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.07 रुपये की बढ़त के साथ 2.6 रुपये हुआ।